के. टी. वर्गीज और अन्य

बनाम

केरल राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 6456/2001)

24 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, लोकेश्वर सिंह पंता और पी. सदाशिवम, जे. जे.]

खान और खनिजः

केरल लघु खनिज रियायत नियम, 1967-छोटे खनिजों का भंडार-लाइमशेल और उन्हें बिक्री के लिए प्रदर्शित करना कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस का अनुदान-खनिज से-केवल अधिकृत उत्खनन परमिट धारकों से खरीदा जाए और यह कि बिक्री केवल घरेलू और कृषि के लिए होगी, राज्य के भीतर उद्देश्य-की शुद्धता-आयोजितः राज्य सरकार के पास नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं है। खुदाई के बाद छोटे खनिज-इस प्रकार, निर्धारित शर्तों को लागू नहीं किया जा सकता था यह निरस्त किया हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957-लघु खनिज रियायत नियम, 1967.

लाइमशेल के व्यवसाय में लगे अपीलकर्ताओं के पास स्टॉक बेचने और प्रदर्शित करने के लिए डीलरों का लाइसेंस था, लघु खनिज के तहत लघु खनिजों की बिक्री के लिए रियायत नियम, 1967 उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो भंडारित किए जाने की अनुमति वाले खनिजों को खरीदा जाना था केवल अधिकृत उत्खनन परमिट धारकों से; और यह कि उन्हें केवल घरेलु और कृषि उददेश्यों के लिए खनिजों को बेचने की अनुमति थी। केवल केरल राज्य अपीलार्थी ने इस आधार पर मूल याचिका दायर की कि सहकारी समितियों के मामले में इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, और इस तरह भेदभाव था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। अभिनिर्धारितः राज्य सरकार सशक्त अधिनियम और राज्य नियमों के तहत ऐसी शर्तें लागू करें और लाइसेंस के प्रावधानों के संदर्भ में जारी किए गए थे। अधिनियम और राज्य के नियमों के बाद से सशर्त लाइसेंस जारी किया गया था, लगाई गई शर्तों के बिना लाइसेंसधारक इसका लाभ नहीं ले सकते थे। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

विक्रेता खनिज नहीं निकालता है। एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का कि राज्य को कोई शक्ति प्रदान नहीं

की गई है, सरकार लघु खनिजों पर नियंत्रण रखेगी खुदाई के बाद, निर्धारित विवादित शर्तों को लागू नहीं किया जा सकता था और हैं तदनुसार मारा गया। [पैरा 12,13] [1211-ए, बी, सी और डी

तमिलनाडु राज्य बनाम एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी 1995 (2) एससीसी 402- पर भरोसा किया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 6456/2001

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के 1998 के डब्ल्यू. ए. सं. 2765 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.1999 से।

पी. कृष्णमूर्ति, रोमी चाको, अहंथम हेनरी, अर्पितगुप्ता और राजीव मेहता, अपीलार्थियों की ओर से।

उत्तरदाताओं के लिए जी. प्रकाश और बीना प्रकाश न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.।

1. इस अपील में केरल उच्च न्यायालय की एकल खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीश द्वारा मूल याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौति दी गई थी।

2. अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंः

अपीलार्थी लाइमशेल के व्यवसाय में लगे हुए हैं। उन्हें आवश्यक विक्रेता लाइसेंस जारी किए गए हैं। केरल लघु खनिज रियायत नियम, 1967 के तहत (खान और खनिज विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 15 के तहत, इसके बाद 'राज्य नियम' के रूप में संदर्भित, 1957 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और लघु खनिज रियायत नियम, 1967 (संक्षेप में 'नियम')। याचिकाकर्ताओं राज्य नियमों के नियम 48-सी के तहत लाइसेंस दिया गया था, के रूप में अपीलार्थी इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। जब अपीलार्थियों को इस अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं दिया गया था। 1997-98, उन्होंने याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ओ.पी.सं. 14269/1997 जिसका निपटारा दिनांक 16.2.1998 के निर्णय द्वारा किया गया था। अपीलकर्ताओं ने उक्त फैसले के खिलाफ एक रिट अपील दायर की और रिट अपील No.547/1998 में इस न्यायालय की खंड पीठ प्रथम प्रत्यर्थी को अभ्यावेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया, अपीलार्थियों द्वारा दायर किया गया। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को मंजूरी दी गई थी, 1998-99 अवधि के लिए उनके लाइसेंस का नवीनीकरण।

3. अपीलार्थियों की शिकायत है कि कुछ शर्तों में जारी करते समय प्रतिबंधों के रूप को शामिल किया गया है। लाइसेंस ऐसी शर्तों में से एक जिस पर अपीलार्थी हमला करते हैं की ओर से, एक अन्य शर्त यह है कि उन्हें बेचने की अनुमति है। केवल केरल राज्य के भीतर खनिज, वह भी घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिए अपीलार्थियों की शिकायत है कि जहाँ तक सहकारी समितियों का संबंध है, अपीलार्थियों के मामले में लगाए गए ऐसे किसी भी प्रतिबंध से पीड़ित वे नहीं हैं। इस प्रकार, अपीलार्थियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों को दिए गए लाइसेंसों में लगाए गए प्रतिबंधों के मामले इस तरह के प्रतिबंधों के अलावा कोई कानूनी मंजूरी नहीं है।

4. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश कि लाइसेंस कुछ शर्तों के अधीन प्रतिबंध दिया गया था। राज्य सरकार को लागू करने का अधिकार था अधिनियम और राज्य नियमों के तहत ऐसी शर्तें और राज्य के नियम लाइसेंस अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में जारी किए गए थे चूंकि लागू की गई शर्तें सशर्त लाइसेंस जारी किया गया था, बिना लाइसेंस के लाइसेंस का लाभ नहीं ले सकते हैं।

5. डिवीजन बेंच ने रिट अपील में इन पहलुओं का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शर्त है कि बिक्री कृषि उद्देश्यों के लिए नियमों के तहत राज्य की शर्त लागू नहीं की जा सकती है।

7. दूसरी ओर राज्य सरकार और उसके लिए उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित शर्तों ने रन निर्धारित किया इस प्रकार हैः

> "लाइमशेल या इसका उपयोग करके बनाए गए उत्पादों को बेचते समय खनिज जो आपको खरीदार को नगद में देना चाहिए अधोहस्ताक्षरित/सहायक द्वारा प्रमाणित ज्ञापन उपयोग से पहले इस कार्यालय के भूविज्ञानी। कृपया ध्यान दें कि कोई भी वैध नकदी के बिना लघु खनिजों की खेप ज्ञापन को अवैध माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी या ऐसा अधिकृत व्यक्ति संबंधित व्यक्ति से खनिज की वसूली करें।"

9. यह कोई गंभीर चुनौती नहीं है ध्यान दिया जाना चाहिए कि शर्त संख्या

10. इसी तरह एक और शर्त लगाई गई थी कि इस प्रकार हैः

"केवल घरेलू और केरल राज्य के भीतर बिक्री के लिए कृषि उद्देश्य"

11. मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि कोई कारण नहीं है ऐसी शर्तों को लागू करने के लिए आधार के रूप में संकेत दिया गया है और लाइसेंसधारियों के लिए ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, जो सही सक्रिय समितियाँ थीं।

12. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विक्रेता खनिज नहीं निकालता है। तमिलनाडु राज्य में बनाम एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी [1995 (2) एस. सी. सी. 402] इस प्रकार इसी तरह की चुनौती पर विचार करते हुए इसे अन्य बातों के साथ-साथ देखा गया। हैः

"17. नियम 8-डी और 19-बी को उक्त में शामिल किया गया था। सरकारी आदेश संख्या 214 दिनांक 10-6-1992 द्वारा नियम। दोनों नियम समान हैं, सिवाय इसके कि नियम 8-डी में धारा ।। जो रैयतवाड़ी भूमि से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार के अंतर्गत आते हैं। यह इतना है, यह पर्याप्त है नियम 19-बी का हवाला देते हुए। वह इस प्रकार हैः

"19 - बी. काले, लाल, गुलाबी, भूरे, हरे रंग का संविधान, सफेद या अन्य रंगीन या बहु रंगीन ग्रेनाइट परमिट धारक आदि

द्वारा उत्खनन किए गए सजावटीपत्थर।

- (1) इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, खनन किए गए काले रंग की बिक्री पर और उससे सरकार और हर वह व्यक्ति जो अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय द्वारा अनुमत, काला, लाल, गुलाबी, धूसर, हरा, सफेद या अन्य रंगीन या बहु रंगीन ग्रेनाइट या किसी भी चट्टान की खुदाई के लिए सजावटी और सजावटी पत्थर के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त, राज्य सरकार या राज्य सरकार के एक अधिकारी या राज्य द्वारा विनियमित किया जाएगा। सरकारी कंपनी या किसी निगम के स्वामित्व में या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित, राज्य के रूप में सरकार इस संबंध में निर्देश दे सकती है।

के. टी. वर्गीज और अन्य वी. केरल राज्य 1210 & अन्य [पासायत, जे।]

(2) कहाँ का उपरोक्त बिक्री द्वारा विनियमित है- (i) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित; राज्य सरकार या राज्य के किसी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार, न्यूनतम मूल्य इस प्रकार होगा।

(ii) राज्य सरकार की कंपनी या निगम राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में, न्यूनतम मूल्य उक्त कंपनी द्वारा

निर्धारित किया जाएगा या निगम, जैसा भी मामला हो सकता हैः बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में इस उप-नियम पर प्रचलित उचित बाजार मूल्य बिक्री के समय को ध्यान में रखा जाएगा।

18. उसी दिन जब नियम 8-डी और 19-बी थे प्रस्तुत किया गया, अर्थात, 10-6-1992, सरकारी आदेश सं. 216 भी जारी किया गया था। इसने निर्देश दिया, के प्रावधानों के तहत दो नियम, कि तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड, एक राज्य सरकारी कंपनी, खनन किए गए काले, लाल, गुलाबी, भूरे, हरे, सफेद या अन्य रंगों की बिक्री को विनियमित करेगी। बहु-रंगीन ग्रेनाइट या उपयोग के लिए उपयुक्त कोई भी चट्टान सजावटी और सजावटी पत्थर।

19. उच्च न्यायालय ने नियम 8-डी और 19-बी को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य सरकार को विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति खनन के बाद ग्रेनाइट का आंतरिक या विदेशी व्यापार। उक्त अधिनियम की धारा 15 में कोई प्रावधान नहीं है। धारा 15 राज्य सरकार को राज्य सरकार की कंपनी या कंपनी को सक्षम बनाने के लिए नियम बनाने का

भी अधिकार नहीं देती है। निगम ग्रेनाइट के लिए न्यूनतम मूल्य तय करेगा।

20. अपीलार्थी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की प्रस्तावना और उसकी धारा 18 को ध्यान में रखते हुए नियम 8-डी और 19-बी वैध थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डी और 19-बी। राज्य की नियम बनाने की शक्ति धारा 15 (ओ) नियम 8 को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक थी।

23. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बाद यह देखना मुश्किल है कि ग्रेनाइट संसाधन ग्रेनाइट की बिक्री को नियंत्रित करके संरक्षित खुदाई करना और उसका न्यूनतम मूल्य तय करना कैसे हो सकता है।

24. उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार नियंत्रण का प्रयोग करेगी। राज्य को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है खुदाई के बाद छोटे खनिज। राज्य सरकार का अधीनस्थ नियम बनाने के रूप में प्राधिकरण, धारा 15 में निर्धारित तरीके से प्रतिबंधित है। नाबालिग की बिक्री और बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने की शक्ति खनिज उपखंड (ओ) की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 15 की धारा (1-ए) यह खंड केवल इससे संबंधित हो सकता

है। पहले से ही खनन किए गए खनिजों की बिक्री को विनियमित करना। खदान और खनन पट्टों के अनुदान का विनियमन और अन्य खनिज रियायतें और यह शक्ति प्रदान नहीं करता है।

13. एम. पी. पी. में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए। कावेरी चेट्टी का मामला (ऊपर) विवादित शर्तें निर्धारित लागू नहीं किया जा सकता था और तदनुसार हैं, गिरा दिया।

14. बिना उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है। लागत के बारे में कोई भी आदेश।

एन. जे.

अपील की अनुमति दी गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपा गुर्जर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।